गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 240
दि. 31.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

बांग्लादेश में एक युग का अंत: पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, राजनीति और संघर्ष से भरा जीवन

(जीएनएस)। ढाका। 30 दिसंबर 2025 की सुबह बांग्लादेश के लिए एक दुखद और ऐतिहासिक क्षण लेकर आई। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और तीन बार सत्ता संभालने वाली बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में ढाका के एवरकेयर अस्पताल में निधन हो गया। लंबी बीमारी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती हुई खालिदा जिया ने अपनी राजनीतिक यात्रा में बीएनपी के लाखों समर्थकों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनीं। उनका जाना केवल एक राजनीतिक नेता के निधन का नहीं, बल्कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा और राजनीतिक संरचना के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है।

खालिदा जिया ने बांग्लादेश की राजनीति में अनगिनत उतार-चढ़ाव देखे। वे 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहीं। इसके अतिरिक्त, वह तीन बार सत्ता में रही और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष के रूप में देश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 के मुक्ति संग्राम से हुई, जब पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। जुलाई से दिसंबर तक वह कैद में रहीं और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद रिहा हुईं। इसके बाद उनका राजनीतिक जीवन लगातार संघर्ष, विरोध और टकराव से भरा रहा।

राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच खालिदा जिया पर कई बार हमले भी हुए। साल 2015 में ढाका में मेयर चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई, जिसमें वे बाल-बाल बचीं। इस दौरान उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी चिंता और आक्रोश देखा गया।

भारत के प्रति खालिदा जिया का रुख अक्सर टकरावपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने का रास्ता देने का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने 1972 की भारत-बांग्लादेश मैत्री संधि के आगे बढ़ाने का विरोध भी किया और कहा कि यह संधि बांग्लादेश को कमजोर कर सकती है। 2018 में एक रैली में उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश को 'भारत का राज्य' नहीं बनने दिया जाएगा। उनकी यह नीति और रुख कई बार विवाद और आलोचना का कारण भी बनी, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे देशभक्ति और संप्रभुता की रक्षा के रूप में देखा।

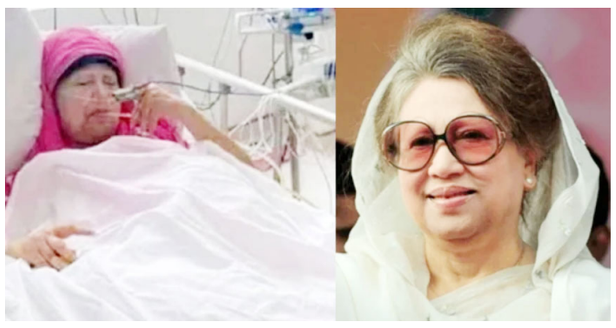

स्वास्थ्य कारणों से खालिदा जिया कई साल विदेश में भी रहीं। इस साल मई में उन्होंने ब्रिटेन से बांग्लादेश वापसी की। इससे पहले जनवरी में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनके विदेश जाने के अनुरोध को मंजूरी दी। शेख़ हसीना की सरकार ने इससे पहले उनके विदेश यात्रा के कम से कम 18 अनुरोधों को खारिज किया था। उनकी विदेश यात्रा और स्वास्थ्य के मुद्दे राजनीतिक चर्चा का विषय बने रहे।

बीएनपी ने उनके निधन के बाद सात दिन का शोक घोषित किया। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय और जिला कार्यालयों में शोक पुस्तिकाएं रखी गईं, ताकि सदस्य और आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की और उनके परिवार एवं बांग्लादेश के लोगों के प्रति हार्दिक सहानुभूति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी दूरदृष्टि और राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रभाव दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में भी हमेशा स्मरणीय रहेगा। राजनीतिक विरासत की दृष्टि से खालिदा जिया ने बांग्लादेश में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम की। उन्होंने बीएनपी को मजबूती दी और राजनीतिक संघर्षों के बावजूद अपने देश की सेवा जारी रखी। उनके कार्यकाल में कई आर्थिक सुधार, अवसंरचना परियोजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उनका नेतृत्व बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक रहा।

खालिदा जिया का व्यक्तित्व साहस, दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक था। उन्होंने हर स्थिति में अपने विचारों और राजनीतिक सिद्धांतों का पालन किया। उनके द्वारा लिए गए कई निर्णय विवादास्पद रहे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों और देशवासियों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ा। उनके नेतृत्व में बीएनपी ने कई चुनावों में सफलता पाई और राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी राजनीतिक यात्रा न केवल बांग्लादेश के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लोकतांत्रिक आंदोलनों, महिला सशक्तिकरण और सत्ता संघर्ष की दृष्टि से उदाहरणीय रही। खालिदा जिया की दूरदर्शिता, साहस और नेतृत्व क्षमता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनके योगदान और विरासत को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा, और उनके प्रयास बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति में मार्गदर्शक बने रहेंगे।

उनकी मौत से बांग्लादेश की राजनीति में खालीपन पैदा होगा, लेकिन उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। खालिदा जिया के समर्थकों ने कहा है कि उनकी विरासत बीएनपी की मजबूती और देश की लोकतांत्रिक प्रगति में हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ विश्वास और नेतृत्व का प्रतीक था। उन्होंने साबित किया कि महिलाओं का नेतृत्व भी किसी भी देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में स्थायी छाप छोड़ सकता है। खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ेगा। उनके विरोधी और समर्थक दोनों ही उनकी राजनीति और निर्णयों पर लंबी चर्चा करेंगे। बीएनपी अब उनके आदर्शों और नीति-निर्देशों को आगे बढ़ाने की चुनौती सामने रखेगी। उनके समर्थकों का मानना है कि खालिदा जिया ने बांग्लादेश की राजनीति में जो योगदान दिया, वह हमेशा याद किया जाएगा और आने वाले वर्षों तक उनके विचार और मार्गदर्शन देश की राजनीति में प्रभाव डालते रहेंगे।

इस तरह, खालिदा जिया का जाना केवल एक नेता का नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लोकतंत्र, महिला नेतृत्व और राजनीतिक स्थायित्व का एक युग खत्म होने के बराबर है। उनके योगदान और संघर्ष का इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसे अध्ययन और प्रेरणा के रूप में अपनाएंगी।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विवाद में बुजुर्ग ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, चुनाव आयोग ने उम्रदराज मतदाताओं के लिए सुनवाई नियमों में बदलाव

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से मंगलवार को एक दुखद घटना सामने आई, जिसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, 82 वर्षीय दुर्जन मांझी ने कथित तौर पर चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना उस समय हुई जब उन्हें एसआईआर के तहत सुनवाई के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय में पेश होने के लिए नोटिस मिला था। मृतक के बेटे कनाई मांझी ने बताया कि उनके पिता को नोटिस मिलने के बाद से अत्यधिक मानसिक तनाव और चिंता बनी हुई थी। उनका कहना था कि दुर्जन मांझी का नाम मसौदा मतदाता सूची में गायब था, जबकि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज था। "मेरे पिता ने जनगणना प्रपत्र जमा किया था, लेकिन उनका नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं हुआ। 25 दिसंबर को सुनवाई के लिए नोटिस मिलने के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों बुलाया गया," कनाई ने मीडिया को बताया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में यह भी कहा कि दुर्जन मांझी की मौत सोमवार को कथित तौर पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और चुनाव अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इस घटना के कुछ ही समय बाद, चुनाव आयोग ने एक नया आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाता, बीमार या दिव्यांग मतदाता को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, यदि उनकी ओर से ऐसा कोई विशेष अनुरोध किया जाता है। यह निर्णय बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर मतदाताओं की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना एसआईआर प्रक्रिया की कठिनाइयों और बुजुर्ग मतदाताओं पर इसके संभावित मानसिक प्रभाव को उजागर करती है। "ऐसे बुजुर्ग मतदाता जिन्हें सुनवाई या नोटिस की प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती है, उनके लिए अतिरिक्त सावधानी और व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता है। चुनाव आयोग का नया आदेश इस दिशा में एक कदम है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करना भी चुनौतीपूर्ण होगा," राजनीतिक विशेषज्ञ डॉ. नरेश वर्मा ने बताया।

स्थानीय लोगों ने कहा कि दुर्जन मांझी एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग थे, जो लंबे समय से अपने वोटर अधिकारों के प्रति सजग थे। उनका कहना है कि बुजुर्गों के लिए एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मानसिक दबाव को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए।

इस दुखद घटना ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर किया है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत लाखों मतदाताओं की सूची में त्रुटियों को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में संवेदनशील समूहों, विशेषकर बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और मार्गदर्शन आवश्यक है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि वे सभी नोटिस प्राप्त बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे नोटिस जारी करने से पहले संबंधित व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।

इस बीच, परिवार और स्थानीय समाज दुर्जन मांझी की अचानक मृत्यु से सदमे में हैं। उनके बेटे कनाई ने कहा, "मेरे पिता केवल अपने अधिकारों के लिए सजग थे। उनका जीवन उनके अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। हम चाहते हैं कि उनकी मृत्यु व्यर्थ न जाए और भविष्य में बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए।"

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घटना चुनाव प्रक्रिया की संवेदनशीलता और प्रशासनिक जिम्मेदारी को दर्शाती है। बुजुर्ग मतदाता अक्सर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन उन्हें नोटिस, सुनवाई और प्रक्रिया में आने वाले तनाव से सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इंडिगो संकट की जांच: मंत्रालय में पैनल ने रिपोर्ट सौंप दी, DGCA के साथ कार्रवाई की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो में हाल ही में हुए उड़ान व्यवधान और देरी के मामले ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक जांच पैनल का गठन किया था, जिसने अब अपनी विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद मंत्रालय ने इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है और इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को बताया कि इंडिगो द्वारा उड़ानों में व्यवधान और देरी के कारणों की पूरी जांच पैनल द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है और इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंत्रालय किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा और यात्रियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। 5 दिसंबर, 2025 को DGCA के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रह्मणे की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति का गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य इंडिगो में हाल ही में हुई उड़ानों की रुकावट और देरी की समीक्षा करना था। समिति को न केवल इस संकट के कारणों का पता लगाना था, बल्कि यह भी देखना था कि एयरलाइन ने अपने परिचालन और यात्री सेवाओं में किन प्रक्रियाओं में कमी की है।

जांच पैनल ने इस दौरान एयरलाइन के परिचालन रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग, कर्मचारी इंटरव्यू और यात्री शिकायतों का विस्तृत विश्लेषण किया। इसके साथ ही एयरलाइन द्वारा संकट प्रबंधन और यात्री सेवा प्रोटोकॉल का भी मूल्यांकन किया गया। पैनल ने यह भी सुझाव दिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इंडिगो और अन्य एयरलाइंस को किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर की शाम को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी। रिपोर्ट में इंडिगो द्वारा फ्लाइट रुकावट और देरी के पीछे तकनीकी कारणों, परिचालन प्रक्रियाओं में खामियों और मानव संसाधन प्रबंधन में कमियों की ओर संकेत किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और समयपालन को ध्यान में रखते हुए कई सुधारात्मक उपाय भी सुझाए गए हैं।

मंत्री राम मोहन नायडू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मंत्रालय पैनल की रिपोर्ट का गंभीरता से मूल्यांकन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों को भरोसा दिलाया जाता है कि भविष्य में इस तरह की असुविधा से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। DGCA इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगा और एयरलाइन के परिचालन मानकों की निगरानी करेगा।

इंडिगो संकट ने देश में हवाई यात्रा की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यह रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पैनल की रिपोर्ट के आधार पर अगर एयरलाइन और DGCA दोनों मिलकर सुधारात्मक कदम उठाते हैं, तो आने वाले समय में हवाई यात्रा और भी सुरक्षित और समयपालक बन सकती है।

इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, इंडिगो में उड़ान व्यवधान और देरी के मामलों के पीछे कई तकनीकी और प्रबंधन कारण हैं। एयरलाइन को अपने फ्लाइट शेड्यूल प्रबंधन, कर्मचारी शिफ्टिंग और रखरखाव प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा। इसके अलावा, यात्रियों के शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करना होगा।

यमन में UAE-सऊदी टकराव: हथियारों पर हवाई हमले ने बढ़ाया तनाव, दक्षिणी यमन में STC का तेज़ विस्तार और आपातकाल

(जीएनएस)। मुकाला। अरब सागर के बीच स्थित यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच गंभीर तनाव सामने आया है। दक्षिणी यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला में सऊदी नेतृत्व वाली कोलिशन ने UAE से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। यह हथियारें अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) को दी जा रही थीं। इस घटना ने न केवल यमन में संघर्ष को और जटिल बना दिया है, बल्कि रियाद और अबू धाबी के बीच पहले से मौजूद मतभेद को भी उजागर कर दिया है।

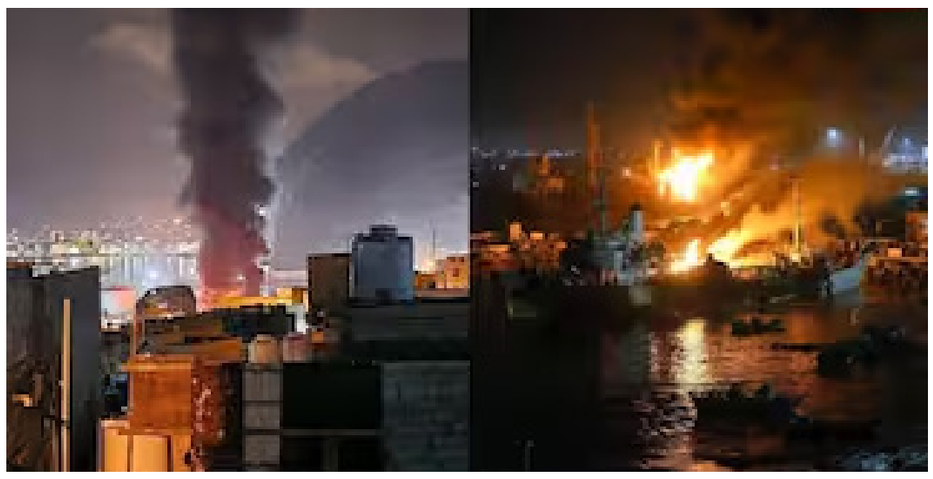

सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, UAE के फुजैरा बंदरगाह से दो जहाज मुकल्ला पहुंचे। इन जहाजों ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर रखा था और बड़ी मात्रा में हथियार तथा बख्तरबंद वाहन STC के लिए उतारे जा रहे थे। सऊदी नेतृत्व वाली कोलिशन ने इन हथियारों को सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा मानते हुए सीमित सैन्य अभियान चलाया। कोलिशन के बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई कोई हताहत या सहायक नुकसान पैदा किए बिना की गई।

इस हमले के तुरंत बाद यमन की हूती-विरोधी ताकतों ने अपने क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया। उन्होंने सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर प्रवेश रोकने का आदेश दिया। केवल सऊदी अनुमति वाले लोगों को ही छूट दी गई। यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल (PLC) के प्रमुख रशाद अल-अलीमी ने UAE के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया और UAE बलों को 24 घंटे में यमन छोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा 72 घंटे का ब्लॉकेड भी लागू किया गया। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने UAE को चेतावनी दी कि यमन में अलगाववादियों को दिया जा रहा समर्थन बेहद खतरनाक है और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि इस टकराव की गहरी वजह दक्षिणी यमन में STC का तेजी से विस्तार है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में STC ने हदरमौत और अल-महरा प्रांतों पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र तेल संसाधनों से समृद्ध हैं और सऊदी अरब व ओमान की सीमाओं से लगे हैं। STC ने इन क्षेत्रों में सरकारी बलों को पीछे धकेल दिया और दक्षिणी यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनका लक्ष्य पूर्व दक्षिण यमन (1967-1990 तक स्वतंत्र) की बहाली है।

UAE ने इस संगठन को खुला समर्थन दिया। हथियार, बख्तरबंद वाहन और अन्य सैन्य सहायता के माध्यम से STC को सशक्त किया गया। 27-28 दिसंबर को UAE के फुजैराह बंदरगाह से दो जहाज मुकल्ला पहुंचे, जहां हथियार उतारे जा रहे थे। इसके तीन दिन बाद, 30 दिसंबर 2025 को सऊदी नेतृत्व वाली कोलिशन ने मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया और इन हथियारों को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने इसे STC के लिए UAE की अवैध मदद बताया।

सऊदी अरब ने STC के इस अभियान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना। दिसंबर 2025 में पहले भी सऊदी ने STC ठिकानों पर चेतावनी वाले हवाई हमले किए और अलगाववादियों को पीछे हटने के लिए कहा। सऊदी का कहना है कि दक्षिणी यमन में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए लाल रेखा है। सऊदी अधिकारियों ने UAE को स्पष्ट किया कि STC को हथियार और अन्य सहायता प्रदान करना गंभीर रूप से खतरनाक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ दशक भर से चल रहे युद्ध में दोनों देश अलग-अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। UAE का STC समर्थन और सऊदी का नाराजगी भरा रुख इस युद्ध को और जटिल बना रहा है। दक्षिणी यमन के तेल-समृद्ध क्षेत्रों और अरब सागर तक पहुंच की रणनीतिक स्थिति इसे और संवेदनशील बनाती है।

इस विवाद ने न केवल यमन की सुरक्षा और स्थिरता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि GCC (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों के भीतर भी तनाव को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के टकराव से क्षेत्रीय राजनीति, तेल आपूर्ति और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण प्रभावित हो सकता है।

सऊदी और UAE के बीच यह तनाव यमन संघर्ष के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला तो दक्षिणी यमन में STC के विस्तार और हथियारों के बंटवारे से सशस्त्र संघर्ष और तेज़ हो सकता है। इस संघर्ष में आम नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय संकट और शरणार्थियों की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

संपादकीय

कांग्रेस के संकट

निस्संदेह, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को फिलहाल बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। चुनाव दर चुनाव उसका दायरा लगातार सिमटता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चुनावी मोर्चे पर भी कांग्रेस के लिए बीत रहा साल निराशाजनक ही रहा है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि, पार्टी ने 'वोट चोरी' मुहिम को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद उसके परंपरागत वोट फिर लौटकर नहीं आए। बल्कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को भी सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिल सका। पार्टी के लिए आने वाला साल एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। आने वाले साल में असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस पर शीर्ष नेतृत्व का आत्मविश्वास से भरा रवैया दिखाना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। इस आयोजन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 'कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, जो सदैव हर कमजोर, वंचित और मेहनतकश व्यक्ति के हितों के लिए खड़ी रही है।' वहीं इस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की कि 'कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है और विचारधाराएं कभी नहीं मरतीं।' लेकिन वास्तव में एक कड़वी सच्चाई यह है कि पार्टी के अस्तित्व पर संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। पार्टी संगठन में असंतोष की आहटें साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। यह असंतोष किस हद जा पहुंचा है, हालिया घटनाक्रम इसकी पुष्टि करता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की कुशल संगठनात्मक रणनीति की प्रशंसा और ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी थी। निश्चय ही आम कार्यकर्ता पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा होगा।

दरअसल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। देखा जाए तो गाहे-बगाहे कांग्रेस संगठन से शीर्ष स्तर पर गहरे तक जुड़े रहे दिग्गज कांग्रेस नेताओं के पार्टी लाइन से हटकर दिए गये बयान पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करते रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का भाजपा व आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति को लेकर चौंकाने वाला बयान सार्वजनिक विमर्श में आया, तो उनके विचारों के प्रति शशि थरूर का संयमित समर्थन करता दृष्टिकोण भी सामने आया, जो यह भी दर्शाता है कि मौजूदा चुनौतियों के बीच कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक शक्ति के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकती। अक्सर कांग्रेस यह दावा भी करती रही है कि इतिहास, मूल्य और विचारधारा उसकी मूल पूंजी हैं। इस पूंजी को चुनावी लाभ में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, यह बयानबाजी से कम और पार्टी में सुधार, संगठन के पुनर्गठन और जनता से प्रभावी ढंग से पुनः जुड़ने की क्षमता पर अधिक निर्भर करता है। ऐसे समय में, जब राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा का एकछत्र वर्चस्व बना हुआ है और यह कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में इसका दबदबा कायम है, भाजपा ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस 'चापलूसों की सेना' है। साथ ही उसे भारतीय लोकतंत्र की 'सबसे कमजोर कड़ी' तक करार दे दिया है। निस्संदेह, यह आलोचना, जो काफी हद तक सच के करीब है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने और मौजूदा स्थिति में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करेगी। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि अपने एक सौ चालीस साल के इतिहास में कांग्रेस एक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ी हुई है। ऐसे में इस पार्टी का पुनरुत्थान भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की संभावनाओं की कुंजी भी साबित हो सकता है। विश्वास किया जाना चाहिए कि अतीत की विफलताओं से सबक लेकर कांग्रेस पार्टी नये साल में नये तेवरों के साथ जनता के दरबार में जाएगी।

2025 में जब जब दुनिया डगमगाई, मोदी ने आगे बढ़कर संभाल लिया

साल 2025 भारतीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विजयगाथा के रूप में दर्ज हो गया। यह वर्ष केवल मोदी की चुनावी सफलताओं का नहीं रहा, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, आर्थिक मजबूती, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के विस्तार का भी साक्षी बना। मोदी ने एक बार फिर यह साबित किया कि उनका नेतृत्व केवल सत्ता संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र को दिशा देने, संकट में निर्णय लेने और दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराने का सामर्थ्य रखता है। 2025 में विभिन्न राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सफलता के पीछे नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति और नेतृत्व की स्पष्ट छाप दिखाई दी। मोदी ने जहां एक ओर सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद को केंद्रीय मुद्दा बनाए रखा, वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, लाभार्थी वर्ग से सीधा संवाद स्थापित करने और विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करने की उनकी रणनीति ने भाजपा को बढ़त दिलाई।

एनडीए के भीतर मतभेदों को साधते हुए मोदी ने सहयोगी दलों को एकजुट रखा और नए सहयोगियों को जोड़कर गठबंधन का विस्तार भी किया। उनका नेतृत्व सहयोगियों में विश्वास पैदा करने वाला रहा, जिससे एनडीए एक मजबूत और अनुशासित राजनीतिक परिवार के रूप में सामने आया।

इसके अलावा, साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रुख पूरी तरह स्पष्ट और सख्त रहा। 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर यह संदेश दे दिया कि भारत अब केवल आतंकी घटना की निंदा तक सीमित नहीं रहेगा। यह कार्रवाई न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया को यह समझाने में सफल रही कि भारत आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर अडिग है। मोदी के इस साहसिक निर्णय ने देशवासियों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि एक निर्णायक शक्ति के रूप में और सुदृढ़ हुई।

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ और दबावों के बावजूद मोदी ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया। रूस के साथ ऐतिहासिक मित्रता को कायम रखते हुए भारत ने ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति के क्षेत्रों में संतुलित नीति अपनाई। मोदी का स्पष्ट संदेश रहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी बाहरी दबाव को हावी नहीं होने देगा। रूस के साथ संबंधों को मजबूत रखना और साथ ही अमेरिका तथा यूरोप के साथ भी संतुलन बनाए रखना मोदी की बहुपक्षीय कूटनीति का उदाहरण है। इसके अलावा, 2025 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। वैश्विक मंदी और महंगाई के दौर में भी भारत ने स्थिरता और विकास दोनों को साधा। मोदी सरकार की नीतियों के चलते महंगाई नियंत्रण में रही, ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम बनी रहीं और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की नीतियों ने रोजगार सृजन और विकास को गति दी।

'जीएसटी उत्सव' के माध्यम से मोदी सरकार ने कर सुधारों की सफलता को जन-जन तक पहुंचाया। जीएसटी ने न केवल कर प्रणाली को सरल बनाया, बल्कि राज्यों की आय बढ़ाने और व्यापार सुगमता में भी अहम भूमिका निभाई। 2025 में जीएसटी संग्रह के नए रिकॉर्ड बने, जिसने सरकार को विकास योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को और बुलंद किया। ग्लोबल साउथ के मुद्दों को विश्व पटल पर मजबूती से उठाते हुए उन्होंने विकासशील देशों की समस्याओं, जलवायु न्याय और समावेशी विकास की वकालत की। उनकी चीन यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा और यह संकेत दिया कि भारत संवाद के साथ-साथ अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है। वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली आमंत्रित कर मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में स्वतंत्र और प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है।

इसके अलावा, 2025 में मोदी ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती दी। धार्मिक स्थलों के विकास के जरिये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों और योग व आयुष के प्रचार ने भारत की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

इसके अलावा, विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना हो या प्राकृतिक आपदाओं में अन्य देशों की मदद करना हो, मोदी सरकार ने हर संकट में तत्परता दिखाई। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और संवेदनशील वैश्विक शक्ति के रूप में उभरी।

बहरहाल, साल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बहुआयामी विजयगाथा का प्रतीक बनकर सामने आया। चुनावी सफलता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और वैश्विक नेतृत्व जैसे मोर्चों पर मोदी ने अपने निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की छाप छोड़ी। यह वर्ष न केवल उनके राजनीतिक कद को और ऊंचा कर गया, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और सामर्थ्य की कहानी भी दुनिया के सामने रख गया।

"एनडीए के भीतर मतभेदों को साधते हुए मोदी ने सहयोगी दलों को एकजुट रखा और नए सहयोगियों को जोड़कर गठबंधन का विस्तार भी किया। उनका नेतृत्व सहयोगियों में विश्वास पैदा करने वाला रहा, जिससे एनडीए एक मजबूत और अनुशासित राजनीतिक परिवार के रूप में सामने आया।

प्रेरणा

क्षण में जागरण की कथा: नागार्जुन और चेतना का दीप

दीक्षा केवल किसी मंत्र का उच्चारण नहीं है, न ही किसी बाहरी विधि का नाम। दीक्षा वास्तव में उस क्षण का नाम है, जब मनुष्य अपने भीतर अंधकार को पहचान कर प्रकाश की ओर मुड़ने का साहस करता है। सिद्ध संत नागार्जुन से जुड़ी यह कथा उसी आंतरिक परिवर्तन की गहरी झलक देती है, जहां एक रानी, एक चोर और एक महात्मा—तीनों अपने-अपने स्तर पर चेतना के अलग-अलग पड़ावों को छूते हैं।

कहा जाता है कि एक रानी नागार्जुन की सिद्धि और उनकी निर्लिप्त चेतना से अत्यंत प्रभावित थी। उसके मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। इसी श्रद्धा के वशीभूत होकर उसने उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। जब नागार्जुन महल पहुंचे, तो वहां वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति का ऐसा वातावरण था, जो सामान्य साधु-संतों को विचलित कर सकता था। पर नागार्जुन के चेहरे पर वही सहज शांति थी, जो वन में भी थी और महल में भी। रानी ने उनके सामने एक अजीब-सा निवेदन रखा। उसने कहा कि वह उनका भिक्षा पात्र चाहती है। यह कोई साधारण मांग नहीं थी। भिक्षा पात्र साधु के जीवन का प्रतीक होता है—उसकी निर्भरता, उसका त्याग, उसका अहंकार-शून्य अस्तित्व। लेकिन नागार्जुन ने बिना किसी संकोच या सवाल के अपना साधारण पात्र उसे दे दिया। उनके भीतर न कोई मोह था, न कोई संकोच। रानी ने बदले में हीरों से जड़ा स्वर्णिम भिक्षा पात्र उन्हें भेंट किया और भावुक होकर कहा कि वह उनके पुराने पात्र की पूजा करेगी।

यहां दो स्तरों पर दो भिन्न चेतनाएं काम कर रही थीं। रानी के लिए वस्तु पवित्र थी, क्योंकि वह किसी महापुरुष से जुड़ी थी। नागार्जुन के लिए न पुराना पात्र पवित्र था, न नया अपवित्र। उनके लिए दोनों समान थे—केवल साधन, केवल वस्तु।

जब नागार्जुन महल से बाहर निकले, तो उनकी दृष्टि सब ओर फैली हुई थी। एक चोर की निगाह उस चमकते, कीमती भिक्षा पात्र पर टिक गई। उसकी आंखों में लालच था, अवसर था। वह सोच ही रहा था कि कैसे उस पात्र को चुरा लिया जाए। नागार्जुन यह सब देख रहे थे। उन्होंने न तो उसे रोका, न ही डांटा। बल्कि उन्होंने स्वयं वह स्वर्णिम पात्र उठाया और मंदिर के बाहर फेंक दिया। यह क्रिया सामान्य बुद्धि को उलझा देती है। कोई संत इतनी कीमती वस्तु यूं ही क्यों फेंक देगा? लेकिन नागार्जुन जानते थे कि वस्तु नहीं, दृष्टि बदलनी है। चोर दौड़कर उस पात्र को उठाने ही वाला था कि अचानक उसके कदम थम गए। कुछ भीतर टूटा, कुछ जागा। उसने पहली बार किसी ऐसे मनुष्य को देखा था, जो धन के सामने बिल्कुल नग्न और निर्लिप्त था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने स्वीकार किया कि वह चोर है, उसकी जिंदगी अंधकार में डूबी हुई है। उसने नागार्जुन के चरण छूने की अनुमति मांगी। जैसे ही उसने चरण छुए, भीतर कोई दीया जल उठा। उसे पहली बार लगा कि जीवन केवल चोरी और भय का नाम नहीं है। उसने प्रश्न किया कि नागार्जुन जैसा बनने में उसे कितने जन्म लगेंगे। यहीं नागार्जुन का वचन कथा को साधारण नैतिक कहानी से उठाकर आध्यात्मिक शिखर पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि यह अभी हो सकता है, इसी क्षण। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि किसी घर में सदियों से अंधकार हो और एक दीया जला दिया जाए, तो अंधकार यह नहीं कह सकता कि वह धीरे-धीरे जाएगा। प्रकाश के आते ही अंधकार चला जाता है। चोर का अगला प्रश्न बहुत मानवीय था। उसने पूछा कि क्या उसे चोरी छोड़नी होगी। नागार्जुन ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई नैतिक उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि यह उसका चुनाव है। यही असली दीक्षा थी—स्वतंत्रता की दीक्षा।

कुछ दिनों बाद वही चोर फिर नागार्जुन के पास आया। लेकिन अब उसकी आंखों में अपराध नहीं था, बल्कि शांति थी। उसने स्वीकार किया कि वह फंस गया है। ध्यान के साथ चोरी संभव ही नहीं है। जैसे-जैसे उसकी चेतना जाग रही थी, चोरी अपने आप छूटती जा रही थी। अब नागार्जुन ने उसके सामने साफ विकल्प रखा—धन या शांति।

यह विकल्प बाहरी नहीं था, यह भीतर का था। चोर ने सिर झुका दिया। उसने कहा कि वह अब अचेतन होकर नहीं जी सकता। उसने नागार्जुन से शिष्य बनाने की प्रार्थना की। तब नागार्जुन ने मुस्कराकर कहा कि उन्होंने उसे दीक्षा पहले ही दे दी है।

इस कथा में दीक्षा कोई औपचारिक संस्कार नहीं है। यह जागरण का क्षण है। यह वह पल है, जब मनुष्य अपने जीवन को स्वचालित आदतों से बाहर निकालकर साक्षी भाव में देखने लगता है। नागार्जुन ने न चोर से चोरी छुड़वाई, न रानी से वैभव। उन्होंने केवल चेतना को स्पर्श किया। यह कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब किसी न किसी रूप में चोर हैं—कभी समय के, कभी प्रेम के, कभी स्वयं के। और हम सब किसी न किसी रूप में रानी भी हैं—वस्तुओं को पवित्र मानने वाले, प्रतीकों में उलझे हुए। नागार्जुन हमें याद दिलाते हैं कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। दीक्षा कोई भविष्य की घटना नहीं है। यह न अगले जन्म का वादा है, न वर्षों की प्रतीक्षा। यह अभी है, इसी क्षण—जब आप जागने का चुनाव करते हैं।

उत्तर-पूर्व के नाजुक मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत

सदियों से, भारत अनगिनत हमलों का निशाना बनता रहा। यह एक प्राचीन सभ्यता थी, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, और मध्य एशिया, ईरान, यूनान आदि के राजा सदा भारत पर हमला करने और उसे लूटने की कोशिश करते रहते थे। गौरी, गजनवी, अब्दाली, मुगल... ये सभी उत्तर-पश्चिम की तरफ से, खैबर दर्रे या ईरान और आज के पाकिस्तान के रास्ते आए। उन्होंने लूटा, अपवित्र किया, नरसंहार किया और कुल मिलाकर उस भूमि को बर्बाद कर दिया जो दौलत से तो भरी थी लेकिन खुद की रक्षा करने में असमर्थ रही।

मुगलों ने एक कदम और आगे बढ़कर यहां पर अपनी जड़ें जमा लीं और सदियों तक राज किया। हालांकि, हमारे दक्षिणी राज्य और साम्राज्य, अपनी दूरी के कारण, इन हमलों को भुगतने से बचे रहे, और वहां लंबे समय तक समुद्र के रास्ते कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने नजदीकी एवं सुदूर पूर्व के देशों के साथ व्यापार किया; उस व्यापार से आखिरकार जो आया, वह था यूरोपीय लोगों के रूप में एक कहीं ज़्यादा घातक हमलावर।

पुराने उत्तर-पूर्वी राज्य (अहोम, मैतेई, कचारी, त्रिपुरी, वगैरह) लंबे समय तक निरंतर आपसी संघर्ष और अशांति की स्थिति में थे। अंग्रेजों ने जो वर्गीकरण थोपा उससे यह पुरानी दरारें और ज्यादा चौड़ी हो गईं। इसमें और इजाफा हुआ बर्मा साम्राज्य के साथ युद्ध और संघर्ष से।

आज मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा वह है उत्तर-पूर्व,क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के इस अपेक्षाकृत दूरदराज कोने में एक बेचैनी पनप रही है, जिसे अगर थामा नहीं गया, तो आने वाले समय में यह इस क्षेत्र में बहुत अस्थिरता का स्रोत बन जाएगा। प्रकृति को शून्यता पसंद नहीं है और यह तब और भी ज़्यादा लागू है जब बात शक्ति और अधिकार की शून्यता भरने की आए। जो आग आज एक छोटी सी झाड़ी की लग रही है, ऐसे में जब कतिपय 'तत्वों' द्वारा हवा दी जा रही हो, तो कल को वह एक बेकाबू दावानल बन सकती है जिसे बुझाने में भारी संसाधन खपाने पड़ेंगे और यह हमें और कमजोर करेगी। यही वह कमजोरी है जो सदियों से हमलावरों को लाती रही है।

आज की तारीख में, दक्षिण अभी भी सुरक्षित है, सिवाय समुद्र के रास्ते होने वाली बड़े पैमाने की तस्करी के। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास तट रक्षक बल और नौसेना है। उत्तर और उत्तर-पश्चिम में नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तान और लद्दाख में चीन की लगातार चुनौती बनी हुई है। यहां संघर्ष की सीमाएं पुरानी हैं, और नागरिक तथा हमारे रक्षा बल हमलावरों और घुसपैठियों की परेशान करने वाली लहरों के उतार-चढ़ाव के आदी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यह एक तेज़ी से क्रमिक विकास करती चुनौती नहीं है, लेकिन शायद समय के साथ यह अपनी मौजूदगी में स्थिर रही है।

पूर्वोत्तर की बात करें तो, हमें इस मोर्चे पर जिस गंभीर और आसन्न खतरे का सामना करना पड़ सकता है, उसे पहचानना होगा। क्योंकि आज हमारे पास पड़ोसी के तौर पर एक अस्थिर म्यांमार है, साथ ही बांग्लादेश भी है, जो पहले हमारा दोस्त था लेकिन अब हमारे प्रति बहुत ज़्यादा बैर पाले हुए है। बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करने और चीन की मदद से उग्रवाद को बढ़ावा देने की ज़रूरत के बारे में नियमित बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान, चीन की गुप्त मदद से उनके साथ है और उन्हें जन, सामान और नैतिक समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत के प्रति अपनी बुरी भावना और कश्मीर के लिए अपने मंसूबे ज़ाहिर करने में जरा हिचक नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर गंभीर अत्याचार हो रहे हैं और निशाना बनाकर हत्याएं हो रही हैं। चीनी ड्रैगन की लगातार बढ़ती मौजूदगी एक खतरा है जो हर दिन बढ़ रहा है।पेंटागन की रिपोर्ट से पता चलता है कि ताईवान की तरह चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश बहुत अहम इलाका है। अरुणाचल सीमा के पार चीन अपने मिलिट्री ठिकानों को तेज़ी से बढ़ा रहा है, जिसमें अग्रिम इलाकों में हवाई अड्डे और हैंगर शामिल हैं। उसने इस इलाके में गांव भी बसाए हैं। याद रखें कि लद्दाख इलाके में हमारी चीन के साथ आमने-सामने की टक्कर हुई है। चीन लगातार ऐसे इलाकों की तलाश में है जहां अग्रिम ठिकाने बनाए जा सकें।

इस बीच, ऐसी खबरें आई हैं कि उल्फा के कई गुट चीन से निकलकर बांग्लादेश जा रहे हैं और अपने जैसी अन्य ताकतों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। ये गुट पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में विगत के आंदोलनों के बचे-खुचे हिस्से को हवा देंगे। हमारे इन राज्यों में पहले से ही अंदरूनी समस्याएं हैं जो हाल के सालों में और बढ़ गई हैं। मसलन, मणिपुर में मैतेई और पहाड़ी जनजातियां- कुकी, नागा वगैरह ऐतिहासिक मतभेदों के कारण आपस में बंटी हुई हैं। ये पहाड़ी जनजातियां मिजोरम, मेघालय और नगालैंड में भी फैली हुई हैं। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है और जबकि वहां सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की भारी मौजूदगी है। इस समस्या को हल करने की ज़रूरत है, और बलों को कार्रवाई की एक स्पष्ट योजना दी जानी चाहिए। मिजोरम, मेघालय और नगालैंड में शरणार्थी कैंप हैं, जो विस्थापित जनजातियों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। इस समस्या में और वृद्धि यह हो सकती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार की सक्रिय मदद से पुरानी आंतरिक गड़बड़ी फिर से शुरू हो सकते हैं। यहां सनद रहे कि इन विद्रोहों को पहले पहल लोगों का समर्थन मिला था। इन इलाकों में लंबे समय तक सामान्य राजनीतिक गतिविधियों पर रोक रही, और इन्हें काबू में लाने में सेना, कूटनीति और नागरिक प्रशासन को दशकों तक मेहनत करनी पड़ी। इन संगठनों के संयुक्त प्रयासों से राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हो पाई। अभी भी कुछ सेवानिवृत्त सेना, नागरिक और पुलिस अधिकारी हैं, जिन्हें उस समय की कई खौफनाक कहानियां याद हैं। दशकों से बहुत खून बह चुका है- हमारे सुरक्षाकर्मियों और इन राज्यों में रहने वाले हमारे लोगों का खून। आइए अब हम अपने राजनीतिक और नागरिक समाज के तमाम संसाधनों का इस्तेमाल इस समस्या को हल करने में करें, ताकि हमें फिर से हथियारों का सहारा न लेना पड़े।

अभियान

नववर्ष की आस्था पर भीड़ का दबाव, वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन को लेकर प्रशासन की सख्त अपील

नववर्ष का आगमन जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे देशभर में उत्साह और उल्लास का माहौल गहराता जा रहा है। साल के आखिरी दिनों में लोग बीते वर्ष की थकान और परेशानियों को पीछे छोड़कर नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकल्पों के साथ करना चाहते हैं। इसी भावना के तहत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा-वृंदावन क्षेत्र हर वर्ष इस समय श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है, जहां भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

इन दिनों वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में हालात ऐसे बन गए हैं कि सुबह से देर रात तक मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरे रहते हैं। गलियों में पैर रखने की जगह नहीं है, सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता है और मंदिर परिसर में हर समय भारी दबाव की स्थिति बनी रहती है। नए साल से पहले और साल के आखिरी दिनों में अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मथुरा पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने साफ शब्दों में अपील की है कि नववर्ष के अवसर पर बिना अत्यंत आवश्यकता के दर्शन की योजना फिलहाल टाल दी जाए।

हर साल की तरह इस बार भी हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु नए साल की शुरुआत बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। किसी की मनोकामना है, किसी का संकल्प, तो कोई केवल ठाकुर जी के चरणों में शीश नवाकर नए वर्ष का स्वागत करना चाहता है। यही कारण है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ही वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इन दिनों प्रतिदिन करीब चार से पांच लाख श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यह संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं।

भीड़ का असर केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वृंदावन की व्यवस्था पर इसका दबाव साफ नजर आ रहा है। संकरी गलियां, सीमित पार्किंग की व्यवस्था और बढ़ते वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। कई बार श्रद्धालुओं को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। आपात स्थिति में एंबुलेंस और पुलिस वाहनों की आवाजाही भी चुनौती बन जाती है। प्रशासन को डर है कि यदि भीड़ इसी तरह बढ़ती रही, तो किसी भी छोटी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है।

इन्हीं हालात को देखते हुए श्री बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से मंदिर न आने की अपील की है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि मंदिर परिसर का आकार सीमित है और एक समय में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकते हैं। जब एक साथ लाखों लोग मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तो अव्यवस्था और धक्का-मुक्की की स्थिति बन जाती है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक साबित हो सकती है।

मथुरा पुलिस ने भी श्रद्धालुओं से संयम और समझदारी बरतने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वृंदावन भले ही परिवार के साथ घूमने और दर्शन करने के लिए एक पवित्र और आकर्षक स्थान है, लेकिन अत्यधिक भीड़ के दिनों में यहां आना सुरक्षित नहीं माना जा सकता। खासकर नए साल की पूर्व संध्या और नववर्ष के दिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो, तो नए साल के कुछ दिन बाद ही यहां आने की योजना बनाएं।

श्री बांके बिहारी मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहां दर्शन की परंपरा अन्य मंदिरों से अलग है। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा है और यहां एक साथ अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। भारी भीड़ होने पर सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं, ताकि दबाव न बढ़े। इसका नतीजा यह होता है कि भक्तों को भगवान के सामने रुककर दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाता। कई श्रद्धालु इस बात से निराश भी होते हैं कि इतनी दूर से आने के बावजूद उन्हें केवल कुछ सेकेंड के दर्शन ही मिल पाए।

भीड़ के कारण कई बार श्रद्धालुओं के बीच असंतोष और तनाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ने की होड़, धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी के बीच कमजोर और बुजुर्ग लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। पूर्व में देश के कई धार्मिक स्थलों पर भीड़ के कारण हादसे हो चुके हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। इसी वजह से लगातार माइक से घोषणाएं की जा रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

प्रशासन का कहना है कि यह एडवाइजरी किसी की आस्था पर रोक लगाने के लिए नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी की गई है। आस्था का मतलब केवल मंदिर पहुंचकर दर्शन करना नहीं होता, बल्कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हालात सामान्य न हों, तो थोड़ी प्रतीक्षा करना भी भक्ति का ही एक रूप माना जा सकता है।

जो श्रद्धालु इन दिनों वृंदावन पहुंच चुके हैं या किसी अत्यंत आवश्यक कारण से यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें, धैर्य बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आपस में सहयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें तथा भीड़ में अनावश्यक आगे बढ़ने से बचें।

स्थानीय दुकानदारों और होटल व्यवसायियों का कहना है कि नए साल के समय वृंदावन में कारोबार भी अपने चरम पर होता है। लेकिन इसके साथ ही व्यवस्थाओं पर दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है। होटल फुल हो चुके हैं, धर्मशालाओं में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है और सड़कों पर हर समय भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों दोनों के लिए संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है।

धार्मिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि भगवान के दर्शन का वास्तविक अर्थ भीड़ में खड़े होकर कुछ सेकेंड देख लेना नहीं, बल्कि मन की शांति और श्रद्धा के साथ जुड़ना है। यदि भीड़ के कारण तनाव और असुविधा हो, तो दर्शन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि श्रद्धालु ऐसे समय में आएं, जब वातावरण अपेक्षाकृत शांत हो और वे पूरे मन से ठाकुर जी के दर्शन कर सकें।

नववर्ष का स्वागत उल्लास, शांति और सुरक्षा के साथ होना चाहिए। यदि आस्था के नाम पर जल्दबाजी और भीड़भाड़ बढ़ेगी, तो खतरे की आशंका भी बढ़ेगी। प्रशासन की अपील यही है कि श्रद्धालु समझदारी से निर्णय लें और सहयोग करें। नए साल के कुछ दिन बाद भी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन उतने ही पवित्र और फलदायी होंगे। थोड़ी प्रतीक्षा से यदि किसी की जान सुरक्षित रहती है, तो यही सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी भक्ति मानी जाएगी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

दोपहिया वाहनों में एबीएस लागू करने का पेच कंपनियों ने समय की मांग की, सड़क सुरक्षा पर सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) को अनिवार्य करने का निर्णय कई कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। समयसीमा के नजदीक आने के बावजूद वाहन निर्माता कंपनियों ने केंद्र सरकार से इस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उद्योग जगत का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इसे तुरंत लागू करना मुश्किल है, और इसके कारण न केवल उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि वाहनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी संभव है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि एक जनवरी की डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। कंपनियों का मुख्य तर्क है कि एबीएस से जुड़े पुर्जों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। यदि एक साथ सभी दोपहिया वाहनों में एबीएस अनिवार्य किया गया तो उत्पादन में व्यवधान आएगा और ग्राहकों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य होगी। इसके साथ ही, छोटे और मझोले वाहन निर्माता इस बदलाव के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हैं। उद्योग ने सरकार को सुझाव दिया है कि इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि सभी कंपनियों को आवश्यक तैयारी का समय मिल सके और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य को भी पूरा किया जा सके।

सड़क सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार की मंशा स्पष्ट है। वर्तमान में एबीएस सुविधा केवल 125 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाली बाइकों तक सीमित है। कम क्षमता वाली बाइकों और स्कूटरों में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (सीबीएस) मौजूद है, जो लगभग 84 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार ने यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं और बाइकिंग सुरक्षा को सुधारने के लिए लिया है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल दोपहिया वाहन चालकों से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या लाखों में है और इनमें ब्रेक फेल होने या नियंत्रण खोने की घटनाएं प्रमुख कारणों में शामिल हैं। एबीएस लागू करने से इन हादसों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।

उद्योग और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच बहस का एक अहम पहलू लागत है। एबीएस लगने से हर वाहन की निर्माण लागत में इजाफा होगा, जिसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और अतिरिक्त लागत की वजह से नई तकनीक को अचानक लागू करना व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा छोटे स्कूटर और मोटरसाइकिल निर्माता पूरी तरह से तकनीकी तौर पर तैयार नहीं हैं और उन्हें सप्लाई और उत्पादन के मामले में समय चाहिए।

सरकार ने अभी तक एबीएस और मानकीकृत हेलमेट को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार नई समयसीमा तय करने सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें चरणबद्ध रूप से नियम लागू करने, छोटे वाहनों को अतिरिक्त समय देने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय पर समुचित कदम नहीं उठाए गए, तो उत्पादन में गिरावट और कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य को भी खतरा होगा। इसके साथ ही, वाहन उद्योग का कहना है कि सरकार को नियम लागू करने से पहले पूरी तैयारी, तकनीकी प्रशिक्षण और सप्लाई नेटवर्क सुनिश्चित करना चाहिए। इससे छोटे और मझोले वाहन निर्माताओं के लिए अचानक आर्थिक दबाव नहीं आएगा और उन्हें नई तकनीक को अपनाने में सहजता होगी। दूसरी ओर सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ जोर दे रहे हैं कि एबीएस एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा है और इसे जल्द से जल्द लागू करना आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा और उद्योग की मांग के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नए नियम की समयसीमा, लागू होने की प्रक्रिया और आवश्यक तकनीकी सहायता की रूपरेखा स्पष्ट करे। अगर यह नियम समय पर लागू हो गया, तो यह देश में सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम होगा, जबकि इसे स्थगित किया गया तो यह उद्योग और ग्राहकों के लिए राहत के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौती भी बनेगा।

विश्लेषकों का कहना है कि एबीएस को दोपहिया वाहनों में अनिवार्य करने से दुर्घटनाओं के दौरान ब्रेक फेल होने की संभावना काफी कम होगी और यह तकनीक बाइक चालकों की सुरक्षा को बढ़ाएगी। लेकिन वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों को संतुलित किया जाएगा।

इस पूरे परिप्रेक्ष्य में वाहन निर्माता कंपनियां और सरकार के बीच चर्चा जारी है। संभावना है कि कुछ दिन के भीतर केंद्र सरकार नई समयसीमा और चरणबद्ध कार्यान्वयन की रूपरेखा घोषित करेगी। आम जनता और वाहन उद्योग दोनों इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यह निर्णय सीधे सड़क सुरक्षा, वाहन कीमतों और उद्योग के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाला है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई: पूर्व IAS अधिकारी समेत 31 आबकारी अफसरों की संपत्ति कुर्क, 2883 करोड़ रुपये की काली कमाई का खुलासा

(जीएनएस)। रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा झटका दिया है। ईडी ने इस कार्रवाई में पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास सहित कुल 31 आबकारी अधिकारियों की संपत्ति कुर्क की है। कार्रवाई के तहत कुल 38.21 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसमें 78 अचल संपत्तियां और 197 चल संपत्तियां शामिल हैं। अचल संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 21.64 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इनमें लग्जरी बंगले, प्रीमियम अपार्टमेंट, व्यावसायिक दुकानें और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि शामिल हैं। वहीं, 197 चल संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 16.56 करोड़ रुपये है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों की जांच और परिसंपत्तियों की निगरानी की प्रक्रिया अभी जारी है।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आबकारी विभाग के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण के चलते एक समानांतर तंत्र संचालित किया जा रहा था। आरोप है कि 'पार्ट-बी' नाम की योजना के तहत बिना किसी रिकॉर्ड के देसी शराब का निर्माण और बिक्री कराई गई। यह शराब सरकारी दुकानों के माध्यम से बेची जाती थी, लेकिन इसमें नकली होलोग्राम और बिना हिसाब की बोतलों का उपयोग किया गया। इस अवैध प्रक्रिया के माध्यम से अधिकारियों और निजी गिरोह ने बड़े पैमाने पर कमाई की और इसे विभिन्न निवेशों और संपत्तियों में लगाया गया।

चार साल की अवधि (2019-2023) में यह गिरोह लगभग 2883 करोड़ रुपये की काली कमाई में शामिल रहा। ईडी ने इस मामले की जांच में सियासतदानों और नौकरशाहों की भागीदारी का भी खुलासा किया। यह गिरोह कई चैनलों के माध्यम से अवैध आय अर्जित करता था, जिसमें कमीशन, बेहिसाब शराब की बिक्री और भ्रष्टाचार के अन्य तरीके शामिल थे।

ईडी की कार्रवाई और पूरक अभियोग प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कई अधिकारियों और गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 26 दिसंबर 2025 को ईडी ने इस मामले में एक पूरक अभियोग शिकायत दर्ज की, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी विभाग में 2019 से 2023 तक हुए बड़े भ्रष्टाचार का ब्यौरा दिया गया। शिकायत में बताया गया कि यह सुसंगठित आपराधिक गिरोह राज्य की शराब नीति का दुरुपयोग कर अवैध कमाई करता था।

जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह चार अलग-अलग चैनलों के माध्यम से आय अर्जित करता था। इनमें एक चैनल देसी शराब की अवैध बिक्री, दूसरा चैनल कमीशन और बोनस, तीसरा चैनल सरकारी दुकानों के माध्यम से नकली बिलिंग और चौथा चैनल संपत्ति और निवेश के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग था।

इस घोटाले ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यदि इस समानांतर तंत्र और भ्रष्टाचार पर समय रहते कार्रवाई की जाती, तो यह काली कमाई इतनी बड़ी नहीं होती। अब तक हुई कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि सरकार और एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने में गंभीर हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के घोटाले न केवल सार्वजनिक धन की चोरी हैं, बल्कि राज्य में शराब नीति और कानून के प्रति आम जनता का विश्वास भी कमजोर करते हैं। ईडी की कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि आगे ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी और अन्य विभागीय अधिकारियों को चेतावनी मिलेगी।

ईडी ने कुर्क की गई संपत्तियों की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी बता रहे हैं कि संपत्तियों की जांच के बाद ही उनका इस्तेमाल या नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही, जिन अधिकारियों पर आरोप है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और

विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला देश में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का एक प्रमुख उदाहरण है। इस घटना ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निगरानी के बिना प्रशासनिक तंत्र में समानांतर तंत्र विकसित हो सकते हैं।

ईडी की इस कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में शराब विभाग और अन्य संवेदनशील विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही आम जनता और निवेशकों का विश्वास राज्य प्रशासन में बढ़ेगा।

एपीएमसी- विजापुर में माल परिवहन हेतु रेलवे सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर दिनांक 29/12/2025 को विजापुर एपीएमसी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य नव-गेज परिवर्तित आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड के माध्यम से स्थानीय कृषि एवं वाणिज्यिक वस्तुओं के परिवहन हेतु रेलवे सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करना था।

बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश द्वारा की गई। सह-अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, अहमदाबाद श्री अनू त्यागी एवं डीडीओ महेसाणा उपस्थित रही। बैठक में कपास उद्योग, अरंडी बीज उद्योग, किसान प्रतिनिधि, तंबाकू संघ, व्यापारी संगठनों, कृषि संघों, माननीय विधायक – विजापुर, तथा एपीएमसी विजापुर के अध्यक्ष एवं निदेशक सहित अनेक गणमान्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान तंबाकू, अरंडी बीज, कपास, गेहूं, आलू एवं खाद्य तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं के रेल परिवहन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। अहमदाबाद मंडल के अधिकारियों द्वारा रेल परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट रूप से समझाया गया, जिसमें इंडेंट डालना, स्टैकिंग, रेक की आपूर्ति, लोडिंग एवं डिलीवरी प्रक्रिया शामिल रही।

पश्चिम रेलवे द्वारा उपलब्ध मिनी रेक, दो-बिंदु/बहु-बिंदु रेक विकल्प, पार्सल एवं वीपीयू (वाहन पार्सल यूनिट) सेवाएं तथा मानक तौल प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त, रेल एवं सड़क परिवहन की लागत की तुलनात्मक प्रस्तुति के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि थोक माल परिवहन में रेल परिवहन अधिक किफायती, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल है।

बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की सराहना की तथा व्यापारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों ने भविष्य में वस्तुओं के परिवहन हेतु रेल सेवाओं को अपनाने की सहमति व्यक्त की।

यह बैठक अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सफल रही, जिससे विजापुर क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने तथा कृषि एवं व्यापार क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की अपेक्षा है।

रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% लाभ की सुविधा

(जीएनएस)। यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवन (RailOne) ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट (R-Wallet) के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% बोनस कैशबैक की सुविधा उपलब्ध है। अब इस पहल को आगे बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया गया है कि रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट के अतिरिक्त सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% की छूट प्रदान की जाएगी। आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग की स्थिति में पूर्व की भांति 3% बोनस कैशबैक की सुविधा जारी रहेगी। यह 3% छूट/लाभ की सुविधा 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान CRIS द्वारा योजना के प्रभाव का फीडबैक मई माह में रेलवे बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आगे की समीक्षा की जा सके। इस निर्णय के अनुरूप रेलवन ऐप में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड की यह पहल यात्रियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करेगी तथा टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी।

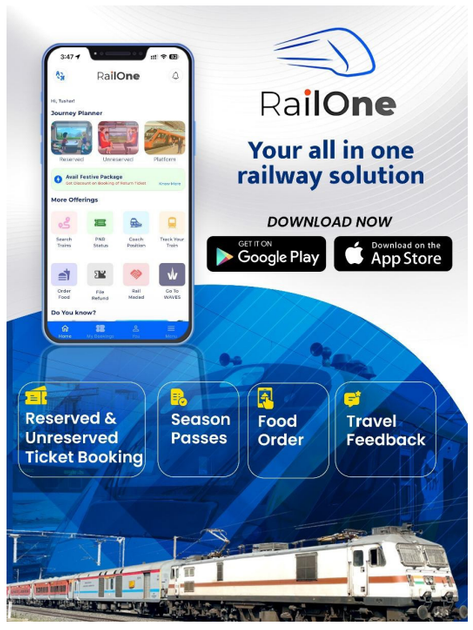

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से राज्य सरकार के वर्ष 2026 के कैलेंडर का अनावरण

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में वर्ष 2026 के कैलेंडर का अनावरण किया। यह कैलेंडर 'आत्मनिर्भर भारत, हमारा गौरव – वोकल फॉर लोकल' थीम पर तैयार किया गया है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए गुजरात की पुरूषार्थ रूपी औद्योगिक प्रगति तथा कला-संस्कृति की समृद्धि को नयनाभिराम तस्वीरों और महत्वपूर्ण संक्षिप्त विवरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में वर्ष 2026 के कैलेंडर का अवलोकन कर प्रसन्नता व्यक्त की। इस कैलेंडर में ऑटोमोबाइल उद्योग, रासायनिक उद्योग, फार्मा सेक्टर, सिरेमिक उद्योग, सेमीकंडक्टर, डायमंड जैसे उद्योगों तथा पाटण का पटोला, कच्छ की हस्तकला, पिठोरा चित्रकला, बांधणी, रोगन चित्रकला, अकीक कारीगरी जैसी गुजरात की विशिष्ट कलाओं को भी प्रदर्शित किया गया है।

इस अवसर पर राज्य स्तर के मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामोद्योग आयुक्त तथा अपर प्रधान सचिव श्री मोहम्मद शाहिद, सूचना निदेशक श्री के. एल. बचाणी, सरकारी मुद्रण एवं छपाई कार्यालय के प्रभारी निदेशक श्री प्रेमसिंह कंवर सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा 01 जनवरी, 2026 से ट्रेन सेवाओं के समय में परिवर्तन

(जीएनएस)। यह परिवर्तन ट्रेन परिचालन को और अधिक सुचारू एवं यात्रियों की सुविधा को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है

पश्चिम रेलवे 1 जनवरी, 2026 से समयपालनता में सुधार के उद्देश्य से दहानू रोड सेक्शन से आने-जाने वाली कुछ लोकल ट्रेन सेवाओं के साथ-साथ कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के समय में परिवर्तन करेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समय परिवर्तन के कारण प्रभावित लोकल ट्रेन सेवाओं तथा मेल/एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेन सेवाओं का विवरण परिशिष्ट-1 (अप दिशा) एवं परिशिष्ट-2 (डाउन दिशा) में प्रदान किया गया है, जिसमें प्रभावित लोकल ट्रेन सेवाओं को विशेष रूप से दर्शाया गया है। समयपूर्व (प्रीपोन) की गई मेल/एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं की सूची अलग से परिशिष्ट-3 में दी गई है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों पर ध्यान दें तथा अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं।

आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड का सीआरएस पश्चिम सर्कल द्वारा संरक्षा निरीक्षण किया गया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आदरज मोटी–विजापुर रेलखंड (39.75 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण (सेफ्टी इंस्पेक्शन) रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम सर्कल द्वारा 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को किया गया। इस निरीक्षण टीम में श्री ई. श्रीनिवास, रेल सुरक्षा आयुक्त (CRS) (पश्चिम सर्कल), श्री वेद प्रकाश, मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण और ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। 30 दिसंबर 2025 को आदरज मोटी–विजापुर सेक्शन में नई परिवर्तित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर 120 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इस दौरान लगभग 40 किमी की दूरी मात्र 20 मिनट में तय की गई। रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा इस परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन को यात्री यातायात के लिए खोलने से पहले ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नलिंग, ब्रिज, ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) सिस्टम, सुरक्षा मानकों और ट्रेन की अधिकतम सुरक्षित गति की पूरी तरह से जांच की गई, जिसमें ट्रैक फिटिंग, बैलास्ट, सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग, OHE की ऊंचाई और अन्य सभी सुरक्षा-संबंधी पहलुओं को सुनिश्चित किया गया। इस रेलखंड में कुल 01 मेजर ब्रिज, 44 माइनर ब्रिज तथा 35 रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया गया है तथा इस रेलखंड में आदरज मोटी, रांधेजा, उनावा–वासन, मकाखड़, लोदरा एवं विजापुर स्टेशन शामिल हैं। आदरज मोटी वर्तमान में एक विद्यमान द्वि-गेज जंक्शन स्टेशन है, जहाँ से आदरज मोटी–गांधीनगर–अहमदाबाद (ब्रॉड गेज) तथा आदरज मोटी–कड़ी–कटोसन (ब्रॉड गेज) लाइनें जुड़ी हुई हैं। गेज परिवर्तन से पूर्व आदरज मोटी–विजापुर एक पृथक मीटर गेज खंड था, जो अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर एकीकृत रेल नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। इस गेज परिवर्तन परियोजना से आदरज मोटी–विजापुर के बीच एकीकृत ब्रॉड गेज रेल प्रणाली उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा पर्यावरण–अनुकूल, सतत और तेज़ रेल संपर्क सुनिश्चित होगा। बेहतर परिवहन सुविधा से दैनिक यात्रियों, पर्यटकों एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन चरित्र पर आधारित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' को मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल सहित मंत्रियों ने रसपूर्वक देखा

अहमदाबाद में 150 कलाकारों द्वारा प्रधानमंत्री के जीवन, विचार और राष्ट्र-निर्माण की यात्रा का प्रेरणादायक प्रस्तुतिकरण

राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रोत्साहक उपस्थिति

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, विचार, कार्य-संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अडिग संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ मंगलवार को आयोजित मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया शो 'नमोत्सव' को मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने देखा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सर्वश्री कनुभाई देसाई, जीतुभाई वाघाणी, कुंवरजीभाई बावळिया, नरेशभाई पटेल, अर्जुनभाई मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य भी सहभागी बने। अहमदाबाद के घुमा स्थित संस्कार धाम में आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बचपन से लेकर राष्ट्र निर्माण की यात्रा तक के विभिन्न पड़ावों को संगीत, नृत्य, नाट्य और आधुनिक मल्टीमीडिया माध्यम द्वारा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

'नमोत्सव' कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने की भावना को सशक्त बनाने का संदेश सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार श्री साईंराम दवे सहित कुल 150 कलाकारों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुति से उपस्थित सभी को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति, सेवा, संकल्प, संस्कार और विकास के मूल्यों को कलात्मक रूप से उजागर किया गया। संस्कार धाम के अध्यक्ष डॉ. आर. के. शाह ने स्वागत करते हुए सभी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने स्वदेशी अपनाने की शपथ भी ग्रहण की।

इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय मंत्रियों सर्वश्री मनीषाबेन वकील, रमेशभाई कटारा, प्रवीणभाई माली, डॉ. जयरामभाई गामित, कमलेशभाई पटेल, स्वरूपजी ठाकोर, पी. सी. बरंडा, मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ल, पूर्व मंत्रिगण, फिल्म निर्देशक श्री आशुतोष गोवारिकर, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव श्री संजय जाजू, श्री अजयभाई पटेल सहित महानुभावों व बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने रसपूर्वक देखा।

एक जनवरी, 2026 से वडोदरा मंडल पर ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू,पंचुअलिटी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर आगामी 1 जनवरी, 2026 से नई समय सारणी लागू की जा रही है। ट्रेनों के परिचालन में पंचुअलिटी को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 77 ट्रेनों का समय प्रीपोन किया गया है जिसमें ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक जल्दी आएंगी। इसी तरह 23 ट्रेनों का समय पोस्टपोन किया गया जिसमें ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट से लेकर 40 मिनट बाद आएंगी। वडोदरा मंडल के नडियाद, आनंद, भरूच, अंकलेश्वर, गोधरा, छायापुरी, एकता नगर सहित अन्य स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के आगमन/ प्रस्थान समय में बदलाव होगा, जिसमें ये ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से पहले या बाद में पहुंचेगी। 69172 भरुच - सूरत मेमू 22930 वडोदरा – दहाणु रोड सुपरफास्ट , 69112 वडोदरा - सूरत मेमू , 69122 गोधरा - वडोदरा मेमू और 69104 आनंद - वडोदरा मेमू को प्रिपोंड कर 5 मिनट पहले किया गया है यानि अब इनका प्रस्थान समय अपने ओरिजनेटिंग स्टेशन से 5 मिनट पहले होगा। यात्रियों की मांग पर अलीराजपुर - प्रतापनगर मेमू को 15 मिनट बाद किया गया है, अब यह ट्रेन अलीराजपुर स्टेशन से 17.15 बजे की बजाय 17.30 बजे जाएगी।

वडोदरा स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 23 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें वडोदरा स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 से 15 मिनट पहले आयेगी, तथा 7 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें वडोदरा स्टेशन पर वर्तमान समय से 5 से 12 मिनट बाद जायेगी।। एकतानगर स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 2 ट्रेनों यानि ट्रेन संख्या 20950 एकतानगर - अहमदाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 09410 एकतानगर - अहमदाबाद स्टीम हेरिटेज स्पेशल को प्रिपोंड किया गया है तथा 2 ट्रेनों यानि ट्रेन संख्या 20945 एकतानगर - हज़रत निजामुद्दीन गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 69206 एकतानगर - प्रतापनगर मेमू को पोस्टपोंड किया गया है। आनंद स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 18 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें आनंद स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 -7 मिनट पहले आयेगी तथा 4 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें आनंद स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 12 मिनट बाद जायेगी। नाडियाड स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 14 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें नाडियाड स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 -10 मिनट पहले आयेगी तथा 2 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें नाडियाड स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट बाद जायेगी। गोधरा स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 4 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है।भरुच स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 15 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें भरुच स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 -7 मिनट पहले आयेगी। अंकलेश्वर स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 5 ट्रेनों को प्रिपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें अंकलेश्वर स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 5 -7 मिनट पहले आयेगी। छायापुरी स्टेशन पर आगमन / से प्रस्थान करने वाली 3 ट्रेनों को पोस्टपोंड किया गया है, यानि ये ट्रेनें छायापुरी स्टेशन पर अपने वर्तमान निर्धारित समय से 2 मिनट बाद आयेगी।

रेलवे की यात्रियों से अपील है कि कृपया नई समय सारणी के अनुसार यात्रा करते समय रेल पूछताछ 139, या वेबसाइट www.wr.indianrailways.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।

18 महीने में सांसद से गुजरात युवा मोर्चा अध्यक्ष तक: हेमांग जोशी का राजनीतिक सफर और तेजी से उठता चेहरा

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात की राजनीति में अचानक उभरता युवा चेहरा हेमांग जोशी ने पिछले 18 महीनों में जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वह किसी राजनीतिक कहानी से कम नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में वडोदरा से बीजेपी ने तत्कालीन सांसद रंजनबेन भट्ट को मैदान में उतारा था। हालांकि जब उन्हें तीसरी बार टिकट मिलने का विरोध हुआ, तो पार्टी को नए उम्मीदवार की तलाश करनी पड़ी। इसी दौरान वडोदरा नगर निगम क्षेत्र की प्राथमिक समिति की उपाध्यक्ष हेमांग जोशी का नाम सामने आया और टिकट मिलने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया।

भाजपा के अंदर हेमांग जोशी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने कई वरिष्ठ नेताओं को चौंका दिया। 34 साल के इस युवा नेता ने टिकट मिलने के साथ ही गुजरात में पार्टी के युवा चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनका तेज़ी से उठना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हेमांग जोशी ने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह अपनी पकड़ मजबूत की, और अब वह गुजरात बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

हेमांग जोशी मूलरूप से पोरबंदर के रहने वाले हैं। उनके पिता के वडोदरा जाने के बाद हेमांग भी 2008 में शहर आ गए। उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (MSU) में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की और उसी दौरान छात्र राजनीति से जुड़ गए। वडोदरा ग्रामीण क्षेत्र की सावली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके जिगर इनामदार के संपर्क में आने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़कर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे राम माधव और शहर अध्यक्ष डॉ. विजय शाह के साथ संपर्क स्थापित किया।

जनवरी 2022 में हेमांग जोशी वीएमसी की स्कूल समिति के उपाध्यक्ष बने और इसी दौरान उनकी राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई। लोकसभा चुनाव 2024 में वडोदरा से बीजेपी के उम्मीदवार बनकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरकर जीत हासिल की। चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनके डॉक्टर का दर्जा भी चर्चा में रहा। कांग्रेस ने उनके 'डॉक्टर' लिखने पर आपत्ति जताई, लेकिन यह विवाद उनके चुनावी सफर को रोक नहीं सका। सांसद बनने के बाद हेमांग जोशी ने राष्ट्रीय राजनीति में भी खुद को स्थापित किया।

लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हेमांग जोशी गुजरात में तेजी से उभरते नेता बन गए। अप्रैल 2024 में वडोदरा से लोकसभा उम्मीदवार बने, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में गुजरात से इकलौते सांसद बने, नवंबर 2025 में SIR का प्रभारी नियुक्त हुए और दिसंबर 2025 में गुजरात बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गए। इस तेजी से उभरते राजनीतिक सफर ने पार्टी के कई पुराने नेताओं को चौंका दिया।

हेमांग जोशी वैष्णव संप्रदाय के संत और महाराज व्रजराज कुमार के शिष्य हैं। वह वडोदरा की वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन (VYO) यूनिट के प्रेसीडेंट भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनके तेजी से उठने में वैष्णव संप्रदाय का आशीर्वाद और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा, उनका राम माधव और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से करीबी रिश्ता भी उनकी तेजी से बढ़ती राजनीतिक पहचान में सहायक रहा।

अब हेमांग जोशी की पहली परीक्षा नगर निगम चुनावों में होने वाली है। सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके कई विदेशी दौरे रहे। अब उन्हें पूरे गुजरात पर फोकस करना होगा। आगामी 2026 के बड़े शहरों के चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगे।

राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि हेमांग जोशी की सफलता का रहस्य उनकी रणनीतिक पोजिशनिंग, संगठन में जुड़ाव, और वैष्णव संप्रदाय का आशीर्वाद है। सांसद के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने और केंद्रीय नेतृत्व के साथ अच्छे संबंधों के चलते उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उनके तेज़ी से उठते प्रभाव ने न केवल पार्टी में बल्कि गुजरात की राजनीति में भी नया समीकरण खड़ा कर दिया है।

वडोदरा की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं की लंबी फेहरिस्त के बीच हेमांग जोशी का उभरना पार्टी और विपक्ष दोनों के लिए चुनौती बन गया है। अगर वह आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति में उनका दायरा और व्यापक हो सकता है। पार्टी के युवा चेहरों में उनका यह स्थान उनके भविष्य के राजनीतिक सफर को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा।

अहमदाबाद के कलाना गांव में झगड़े का तनाव, मामूली विवाद बना बड़े पथराव का कारण; 42 लोग हिरासत में

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद जिले के कलाना गांव में मामूली विवाद अचानक बड़े झगड़े में बदल गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विवाद की शुरुआत कुछ छोटे मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी से हुई थी। देखते ही देखते यह मामूली झगड़ा हिंसक मोड़ ले गया और दोनों गुटों के लोग एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। इस घटना ने गांव के लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया।

स्थानीय पुलिस के अनुसार, पथराव में किसी के गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने झगड़े में शामिल लोगों की पहचान कर 42 लोगों को हिरासत में ले लिया। यह सभी लोग दोनों गुटों से संबंधित हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि झगड़े की असली वजह सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

गांव में तनाव के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल प्राथमिक कदम के रूप में सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनके बयान लिए जा रहे हैं। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने गांववासियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

यह घटना सामाजिक और सामुदायिक तनाव को भी उजागर करती है। कलाना गांव में पहले भी कभी-कभार छोटे-मोटे विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार झगड़ा इतनी तेजी से बढ़ा कि पथराव जैसी हिंसक घटना सामने आई। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी कहासुनी कभी-कभी सांप्रदायिक या समूहगत तनाव में बदल जाती है, और प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ता है।

इस घटना की पृष्ठभूमि में यह भी देखा गया कि विवाद के समय गांव के कुछ लोग बाहर से भी शामिल हो गए थे, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए 42 लोगों से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगा कि पथराव किसने शुरू किया और किसका इसमें मुख्य रोल था।

पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान में स्थानीय और पड़ोसी जिलों के लोग भी शामिल हैं। गांववासियों के सहयोग से ही पुलिस ने प्रारंभिक नियंत्रण हासिल किया। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंसा के दौरान कोई गंभीर नुकसान न हो और गांव में जल्द से जल्द सामान्य जीवन बहाल हो।

इस घटना के बाद प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए गांव में सतत निगरानी और सामाजिक समझौता प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय पंचायत और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इसी बीच, राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध फैक्टरी पर कार्रवाई का उदाहरण भी सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने अहमदाबाद एटीएस के सहयोग से भिवाड़ी के पास एक अवैध दवा निर्माण फैक्टरी का भंडाफोड़ किया, जहां चिंता और घबराहट संबंधी विकारों की दवा बनाने का आरोप था। इस कार्रवाई में लगभग 30 लाख रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह मामला यह दर्शाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिंसा और अवैध गतिविधियों दोनों ही प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं।

कलाना गांव की घटना और राजस्थान में अवैध दवा फैक्टरी की गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि राज्य प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप, जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से ही समुदाय में शांति कायम रखी जा सकती है।

01 जनवरी 2026 से अहमदाबाद मंडल पर नया टाइम टेबल लागू

अहमदाबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों से चलने/गुजरने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर आगामी 01 जनवरी, 2026 से नई समय सारणी लागू की जा रही है। इसमें कुछ ट्रेनों की गति बढ़ाई जा रही है,जिससे यह ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से पहले गंतव्य पर पहुंचेगी।

इस बार अहमदाबाद मंडल से होकर जाने वाली 85 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है साथ ही 23 ट्रेनों के यात्रा में लगने वाले समय में 05 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की कमी की गई है। ट्रेनों की गति बढ़ाए जाने के फलस्वरूप यात्री ट्रेनों के परिचालन समय में कमी आई है। इसका पूरा लाभ यात्रियों को मिलेगा व उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने में समय की बचत होगी।

अहमदाबाद डिविजन पर इस दौरान विभिन्न स्टेशनों पर 110 ट्रेनों का समय प्रीपोन किया गया है जिसमें ट्रेनें अपने पहले के समय से 5 मिनट से लेकर 40 मिनट तक जल्दी आएंगी। इसी तरह 57 ट्रेनों का समय पोस्टपोन किया गया जिसमें ट्रेनें अपने पहले के समय से 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक देरी से आएंगी। अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, पाटन, भीलड़ी,उंझा, सिद्धपुर, गांधीनगर, कलोल, वीरमगाम, गांधीधाम, हिम्मतनगर, हलवद, ध्रांगध्रा, सामाख्याली, भुज सहित अन्य स्टेशनों के समय में बदलाव होगा जिसमें ये ट्रेनें अपने वर्तमान निर्धारित समय से पहले या बाद में पहुंचेगी। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

प्रारंभिक स्टेशन से समय से पूर्व प्रस्थान करने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

1.ट्रेन संख्या 12932 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी डबल डेकर एक्सप्रेस अहमदाबाद से 05.50 बजे के स्थान पर 05.45 बजे प्रस्थान करेगी।

2.ट्रेन संख्या 22962 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद से 06.10 बजे के स्थान पर 06.05 बजे प्रस्थान करेगी।

3.ट्रेन संख्या 19316 असारवा-इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस आसारवा से 14.25 बजे के स्थान पर 14.10 बजे प्रस्थान करेगी।

4.ट्रेन संख्या 12982 असारवा-जयपुर एक्सप्रेस आसारवा से 20.00 बजे के स्थान पर 19.55 बजे प्रस्थान करेगी।

5. ट्रेन संख्या 69249 साबरमती-कटोसन रोड मेमू साबरमती से 06.45 बजे के स्थान पर 06.30 बजे प्रस्थान करेगी।

6.ट्रेन संख्या 79435 साबरमती-पाटन डेमू साबरमती से 09.05 बजे के स्थान पर 09.00 बजे प्रस्थान करेगी।

7.ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस साबरमती से 22.15 बजे के स्थान पर 22.05 बजे प्रस्थान करेगी।

8.ट्रेन संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस साबरमती से 18.10 बजे के स्थान पर 17.55 बजे प्रस्थान करेगी।

9.ट्रेन संख्या 79433 साबरमती-पाटन डेमू साबरमती से 18.20 बजे के स्थान पर 18.05 बजे प्रस्थान करेगी।

10.ट्रेन संख्या 69207 गांधीनगर कैपिटल-वारेठा मेमू गांधीनगर कैपिटल से 18.00 बजे के स्थान पर 17.50 बजे प्रस्थान करेगी।

11.ट्रेन संख्या 19119 गांधीनगर कैपिटल-वेरावल एक्सप्रेस गांधीनगर कैपिटल से 10.25 बजे के स्थान पर 10.20 बजे प्रस्थान करेगी।

12.ट्रेन संख्या 19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस गांधीनगर कैपिटल से 10.05 बजे के स्थान पर 10.00 बजे प्रस्थान करेगी।

13. ट्रेन संख्या 22484 गांधीधाम-भगत की कोठी एक्सप्रेस गांधीधाम से 21.40 बजे के स्थान 21.30 बजे प्रस्थान करेगी।

14.ट्रेन संख्या 14894 पालनपुर-जोधपुर एक्सप्रेस पालनपुर से 04.35 बजे के स्थान पर 04.30 बजे प्रस्थान करेगी।

15. ट्रेन संख्या 82902 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से 06.40 बजे के स्थान पर 06.35 बजे प्रस्थान करेगी।

प्रारंभिक स्टेशन से देरी से प्रस्थान करने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

1.ट्रेन संख्या 12957 साबरमती-नई दिल्ली स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस साबरमती से 19.10 बजे के स्थान पर 19.20 बजे प्रस्थान करेगी।

2.ट्रेन संख्या 19415 साबरमती-श्री माता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस साबरमती से 20.55 बजे के स्थान पर 21.35 बजे प्रस्थान करेगी।

3.ट्रेन संख्या 74842 भीलड़ी- जोधपुर डेमू भीलड़ी से 14.45 बजे के स्थान पर 15.10 बजे प्रस्थान करेगी।

टर्मिनल स्टेशन पर समय से पूर्व आगमन करने वाली कुछ ट्रेनें

1.ट्रेन संख्या 12901 दादर-अहमदाबाद गुजरात मेल एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन पर 05.50 बजे के स्थान पर 05.40 बजे आगमन करेगी।

2. ट्रेन संख्या 19315 इंदौर-असारवा वीरभूमि एक्सप्रेस असारवा पर 10.50 बजे के स्थान पर 10.15 बजे आगमन करेगी।

3. ट्रेन संख्या 69249 साबरमती-कटोसन रोड मेमू कटोसन रोड पर 08.05 बजे के स्थान पर 07.45 बजे आगमन करेगी।

4.ट्रेन संख्या 69207 गांधीनगर कैपिटल-वारेठा मेमू गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर 20.50 बजे के स्थान पर 20.30 बजे आगमन करेगी।

टर्मिनल स्टेशन पर समय के बाद आगमन करने वाली कुछ ट्रेन

1.ट्रेन संख्या 15269 मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस साबरमती स्टेशन पर 06.45 बजे के स्थान पर 07.25 बजे आगमन करेगी।

2.ट्रेन संख्या 20969 वलसाड-वडनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वडनगर स्टेशन पर 13.00 बजे के स्थान पर 13.10 बजे आगमन करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की 2026 के प्रारंभ पर राज्य को अभिनव भेंट

गिफ्ट सिटी में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (आईएआईआरओ) की स्थापना की जाएगी

▸▸ गुजरात सरकार, भारत सरकार तथा उद्योगों की भागीदारी से पीपीपी मॉडल पर 1 जनवरी 2026 से कार्यरत होगा आईएआईआरओ : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी

▸▸ गुजरात ने पीपीपी मॉडल पर इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने वाले देश के प्रथम राज्य का गौरव प्राप्त किया

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में एआई के उपयोग से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक कदमों से लोगों के जीवन में परिवर्तन की मंशा साकार करने की दिशा में गुजरात का एक और नूतन कदम

(जीएनएस)। गांधीनगर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अधिक सुदृढ़ बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर एआई इकोसिस्टम को गति देने की पहल वर्ष 2026 के प्रारंभ पर गुजरात ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में की है। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से राज्य सरकार, भारत सरकार तथा इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस (आईपीए) की त्रिपक्षीय भागीदारी से इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (आईएआईआरओ) की स्थापना करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में गुजरात ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में पीपीपी मॉडल पर इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने वाले देश के प्रथम राज्य का गौरव प्राप्त किया है।

गिफ्ट सिटी में आगामी 1 जनवरी 2026 से यह आईएआईआरओ स्पेशल परपज व्हीकल के रूप में कार्यरत किया जाएगा। इस इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत नॉन-प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट के रूप में किया जाएगा।

इतना ही नहीं; इस प्रोजेक्ट के लिए प्रथम पाँच वर्ष के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें राज्य व केन्द्र सरकार तथा निजी भागीदार; तीनों का 33.33 प्रतिशत योगदान रहेगा।

इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस आईएआईआरओ के लिए एंकर निजी भागीदारी के रूप में जुड़ा है और वर्ष 2025-26 के लिए 25 करोड़ रुपए का योगदान देने वाला है। इस आईपीए में सिप्ला, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा जैसी कंपनियों सहित लगभग 23 अग्रणी फार्मा कंपनियों का समावेश होता है। गुजरात की यह पहल भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया एआई मिशन तथा राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एआई एक्शन प्लान के उद्देश्यों के साथ सुसंगत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा अन्य सेवाओं में परिवर्तनकारी सुधारों से लाखों लोगों के जीवन को अधिक सरल बनाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गति वेगवान बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने एआई टास्कफोर्स का गठन भी किया है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब आईएआईआरओ को एआई के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी हब बनाने की मंशा रखी गई है। आईएआईआरओ की मुख्य गतिविधियों में अद्यतन एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई आधारित प्रोडक्ट्स तथा सॉल्यूशन्स के विकास एवं शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों, स्टार्टअप्स तथा सरकार के बीच सहयोग को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त; इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आईपी) क्रिएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा पॉलिसी बेस्ड रिसर्च पर भी आईएआईआरओ फोकस करेगा। आईएआईआरओ हाइब्रिड कम्प्यूट मॉडल अंतर्गत कार्य करेगा। इसमें ऑन-प्रिमाइसेस जीपीयू इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इंडियाएआई क्लाउड जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म्स का समन्वय भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में गुजरात की यह पहल एआई के लिए कुशल एवं भावी मानव संसाधन तैयार करने के साथ-साथ एआई सेक्टर में भारत को ग्लोबल कम्पीटिटिव लीडर के रूप में स्थापित करेगी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए गुजरात का स्थान अधिक मजबूत बनाएगी।

सोना वायदा में 1438 रुपये और चांदी वायदा में 11531 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 18 रुपये की वृद्धि

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 48360.65 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 242250.56 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 37779.40 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35109 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 290619.15 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 48360.65 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 242250.56 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 35109 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1992.1 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 37779.40 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 136000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 136650 रुपये और नीचे में 135292 रुपये पर पहुंचकर, 134942 रुपये के पिछले बंद के सामने 1438 रुपये या 1.07 फीसदी की तेजी के संग 136380 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 2031 रुपये या 1.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 109742 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 212 रुपये या 1.57 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 13682 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जनवरी वायदा 133185 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 134256 रुपये और नीचे में 132853 रुपये पर पहुंचकर, 1385 रुपये या 1.04 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 133980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 134292 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 135308 रुपये और नीचे में 134261 रुपये पर पहुंचकर, 133076 रुपये के पिछले बंद के सामने 1649 रुपये या 1.24 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 134725 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 231100 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 237225 रुपये और नीचे में 231100 रुपये पर पहुंचकर, 224429 रुपये के पिछले बंद के सामने 11531 रुपये या 5.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 235960 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 10940 रुपये या 4.84 फीसदी की बढ़त के साथ 236760 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 10978 रुपये या 4.86 फीसदी की तेजी के संग 236800 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 8684.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 60.2 रुपये या 5.01 फीसदी की तेजी के संग 1261.9 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 2.1 रुपये या 0.69 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 306.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 4.15 रुपये या 1.43 फीसदी की मजबूती के साथ 294.35 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 5.9 रुपये या 3.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 194.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1870.68 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5254 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5270 रुपये और नीचे में 5231 रुपये पर पहुंचकर, 18 रुपये या 0.34 फीसदी बढ़कर 5258 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 18 रुपये या 0.34 फीसदी की मजबूती के साथ 5258 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 356.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 361.2 रुपये के दिन के उच्च और 353.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 357.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 50 पैसे या 0.14 फीसदी के सुधार के साथ 357.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 20 पैसे या 0.06 फीसदी के सुधार के साथ 357.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 984.5 रुपये पर खूलकर, 38.7 रुपये या 3.97 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1013 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 17385.91 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20393.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 8014.04 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 354.94 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 25.66 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 290.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 284.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1570.24 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19303 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 83919 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 24336 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 391408 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 42519 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17180 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40637 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 110710 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20021 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 33810 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 34650 पॉइंट पर खूलकर, 35331 के उच्च और 34650 के नीचले स्तर को छूकर, 293 पॉइंट बढ़कर 35109 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 3.7 रुपये की बढ़त के साथ 117.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 20 पैसे की नरमी के साथ 27.6 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 90.5 रुपये की बढ़त के साथ 396.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 249000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3435 रुपये की बढ़त के साथ 10700 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 21.57 रुपये की बढ़त के साथ 66.24 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 12 पैसे की नरमी के साथ 12.2 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 9.2 रुपये की गिरावट के साथ 113.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 20 पैसे की नरमी के साथ 24.35 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 114 रुपये की गिरावट के साथ 62.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1568.5 रुपये की गिरावट के साथ 3038 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 21.36 रुपये की गिरावट के साथ 24.75 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.09 रुपये की गिरावट के साथ 10.15 रुपये हुआ।